



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ज्येष्ठ 15, 1939

No. 147]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/JYAISTHA 15, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

एसएसआर - 12/2017

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और यू.ए.ई. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड" के आयात पर पुनरीक्षा जांच की शुरुआत।

**फा. सं. 7/8/2017-डीजीएडी.**—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और यू.ए.ई., (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम सं. 14/45/2000-डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च, 2012 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम सं. 32/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 7 जून, के अनुसार शुल्क लागू किए थे। प्राधिकारी की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं. 14/45/2010-डीजीएडी, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के अनुसार प्रकाशित की गई थी। जांच परिणामों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 6/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी निर्णायक शुल्क लगाए थे।

2. जबकि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) की शर्तों में लागू किये गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले रद्द न किया गया हो, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से 5 वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी होना चाहिए और प्राधिकारी को यह समीक्षा

करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। उपर्युक्त के अनुसरण में, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से भली-भांति किए गए महत्वपूर्ण अनुरोध के आधार पर यह पुनरीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति के कारण और क्षति जारी रहेगी या उनकी पुनरावृत्ति होगी।

3. और जबकि मै. सेंट-गोबाइन इंडिया प्रा. लि. (जिसे इसके बाद “याचिकाकर्ता” कहा जाएगा) की अधिनियम और नियमों के अनुसरण में, चीन, इंडोनेशिया, थाइलैंड और यू.ए.ई. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहने और उनकी पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप लगाते हुए, शुल्कों को और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए “प्लेन जिपसम प्लास्टर बोर्ड” के आयात पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

#### विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “सभी प्रकार की मोटाई और परिमाण के प्लेन जिपसम प्लास्टर” हैं किन्तु इनमें निम्न शामिल नहीं हैं:

- (1) 5 प्रतिशत तक और उसके सहित पानी को सोखने वाले जिप्सम बोर्ड (नमी रोधक बोर्ड)
- (2) मोटाई की प्रति मिलीमीटर में आने आड़ी दिशा में 24 न्यूट्रॉन के न्यूनतम ब्रेकिंग लोड और दीर्घावलंब दिशा में 50 न्यूट्रॉन वाले जिपसम बोर्ड (“इम्पैक्ट प्रतिरोध बोर्ड” या अग्नि प्रतिरोधक बोर्ड)।
- (3) फायर बोर्ड
- (4) फायर हीट बोर्ड
- (5) जिपसम सीलिंग बोर्ड आर्द्रतारोधक सहित
- (6) ई सी एच ओ बोर्ड
- (7) हीट बोर्ड
- (8) संचालकतारोधी बोर्ड या वेदर बोर्ड
- (9) थर्मल बोर्ड
- (10) श्वेत फिल्म में सीलड अल्युमिनियम किनारों के साथ जिपसम सीलिंग बोर्ड

5. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय शीर्ष 68091100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, संबद्ध वस्तुएं टैरिफ शीर्ष 68091900 के तहत भी आयातित की जा रही हैं। हालांकि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान जांच, प्रवृत्त शुल्क की निर्णायक समीक्षा होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद वही बना रहेगा जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

6. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशेषताओं, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और प्रयोक्ता उन्हें अंतर्बदल रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

#### घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. निर्णायक समीक्षा के लिए अनुरोध मै. सेंट-गोबाइन इंडिया प्रा.लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का बड़ा भाग उत्पादित करता है। इसलिए, आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना गया है और उक्त सहभागी कंपनियों को क्षति जांच के प्रयोजन हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग माना गया है।

#### शामिल देश

8. प्रवृत्त शुल्क चीन जन.गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और यू.ए.ई. के विरुद्ध हैं। अतः यह निर्णायक समीक्षा में केवल चीन जन.गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और यू.ए.ई. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर प्रवृत्त शुल्क शामिल होंगे।

**निर्णायक समीक्षा की प्रारंभिक जांच**

9. स्वयं संतुष्ट होने पर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर, पाटन के जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए, प्राधिकारी ने इस बात की पुनरीक्षा करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्क को समाप्त करने से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहेगा या उनकी पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के विरुद्ध प्रवृत्त निश्चित शुल्कों को निरंतर लगाने की जरूरत की समीक्षा के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसरण में, एतद्वारा जांच आरंभ की है।

**प्रक्रिया**

10. समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/45/2010-डी जी ए डी दिनांक 15 जनवरी, 2013 के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिसके अनुसार चीन जन.गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और यू ए ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लेन जिपसम बोर्डों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई है।

11. इस समीक्षा में ऊपर बताई गई नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य होंगे।

**जांच की अवधि**

12. जांच की अवधि जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2016 (12 महीने) है और क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अवधि अर्थात् अप्रैल, 13 से मार्च, 14, अप्रैल, 2014 से मार्च, 15, अप्रैल, 2015 से मार्च, 16 और जांच अवधि विचारित की जाएगी।

**सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध वस्तुओं से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और भारत में घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:—

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**  
**वाणिज्य विभाग**  
**कमरा नं. 01, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

15. प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करते समय संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को घरेलू बाजार में और भारत को और अन्य देशों को निर्यात में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री से संबंधित बाजार स्थिति की व्यापकता का प्रदर्शन करना होगा। इस प्रयोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं :-

- क. मूल्य, लागत, कच्ची सामग्री सहित इनपुट, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्री और निवेश से संबंधित निर्णय उल्लेखनीय राज्य हस्तक्षेप के बिना है और मुख्य इनपुट की मौसम की लागत उल्लेखनीय रूप से बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विरूपण के लिए पीड़ित नहीं हैं।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन और संपत्ति कानून के अध्वधीन है जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थायित्व प्रदान करता है।
- घ. विनिर्दर दर में परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

**समय-सीमा**

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त

नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

#### अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियाँ और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियाँ प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

SSR - 12/2017

(Sunset Review)

**Subject: Initiation of Review investigation on imports of "Plain Gypsum Plaster Boards", originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE.**

**F. No. 7/8/2017-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Plain Gypsum Plaster Boards", (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE (hereinafter referred to as subject Countries). The authority vides its preliminary findings No. 14/45/2010-DGAD dated the 19th March, 2012, recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the Subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 32/2012-Customs (ADD) dated the 7th June. The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/45/2010-DGAD dated 15th January, 2013. On the basis of the findings, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 6/2013-Customs (ADD) dated 12th April, 2013.

2. WHEREAS in terms of Section 9A (5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And whereas, a petition has been filed by M/s Saint-Gobain India Private Limited (hereinafter referred to as 'petitioner') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of "Plain Gypsum Plaster Boards" for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the above goods originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE.

#### **Product under Consideration**

4. The product under consideration in the present application is "Plain Gypsum Plaster Boards of all thicknesses and dimensions but excluding the following:

- (i) Gypsum Boards having water absorption up to and including 5% (Moisture Resistant Boards)
- (ii) Gypsum Boards having a minimum breaking load of 24 neutrons in the transverse direction and 50 neutrons in the longitudinal direction per millimeter of thickness (Impact Resistant Boards" or "Fire Resistant Boards).
- (iii) Fire Boards
- (iv) Fire Heat Boards
- (v) Gypsum Ceiling Boards with Moisture Barrier
- (vi) ECHO Boards
- (vii) Heat Boards
- (viii) Anti-modal Boards or Weather Boards
- (ix) Thermal Boards
- (x) Gypsum Ceiling Boards with Aluminium Edges Sealed in White Film

5. The product under consideration is classified under chapter heading 68091100. However, the subject goods are also being imported under tariff headings 68091900. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Present investigation, being a sunset review of the duty in force, the products under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

6. Petitioner has submitted that the subject goods produced by them are like article to the goods imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

#### **Domestic Industry and Standing**

7. The request for the sunset review has been filed by M/s Saint-Gobain India Private Limited. The applicant accounts for a major proportion of the domestic production of the subject goods. Therefore, the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the above participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules for the purpose of injury investigation.

**Countries involved**

8. The duties are in force against China PR, Indonesia, Thailand, and UAE. Therefore, this sunset review will cover the duty in force on the subject goods originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE only.

**Initiation of Sunset Review**

9. Having satisfied itself, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, the Authority hereby initiates an investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review whether revocation of the duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the subject countries and continuation or recurrence of injury to the domestic industry, and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**Procedure**

10. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. No. 14/45/2010-DGAD dated 15th January, 2013 recommending continuation of anti-dumping duty on import of Plain Gypsum Plaster Boards originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand and UAE.

11. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Period of Investigation**

12. The period of investigation is January 2016 to December 2016 (12 months) and for the purpose of injury determination, the period i.e., April 2013 to March14, April 2014 to March15, April 2015 to March16 and the POI will be considered.

**Submission of Information**

13. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry in India are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Ministry of Commerce and Industry,  
Department of Commerce  
Room No. 01, 4th Floor Jeevan Tara Building,  
Parliament Street New Delhi-110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

15. While submitting the questionnaire response, producers/exporters in the subject countries may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may provide sufficient information on the following:

- a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- b. Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. change rate conversions are carried out at the market rate.

**Time Limits**

16. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need for continuation, or otherwise, of the anti-dumping measures, within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of Information on Confidential Basis**

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof, or without a good cause statement on the confidentiality claim, may not be taken on record by the Authority. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority